उन के संबंध में मंत्री महोदय ने नहीं बतलाया कि उन की स्थिति क्या है, कब तक देश में आ जायेंगे और कब तक वह लग जायेंगे ?

श्री राज बहादुर : वह दोनों शौर्ट वेव के नहीं बल्कि मीडियम वेव के ट्रांसमीटर्स हैं। उन के बारे में आशा है कि उन का सामान सन् 67 के आखिर में या 68 के आरम्भ में आ जायेंगे और वे या तो 68 के मध्य में या 68 के आखिर तकदोनों चालू हो जायेंगे, एक कलकत्ते में और एक राजकोट में।

श्री भागवत झा आजाद : असम्पुष्ट समाचारों के अनुसार हमारे पूर्वी सीमाक्षेत्र में चीनियों के लगभग 50 ट्रांसमीटर्स काम कर रहे हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकारी सूचना के अनुसार उन की संख्या क्या है और उन का जवाब देने के लिए हमारी योजना इस पूर्वी सीमाक्षेत्र में कितने ट्रान्समीटर्स स्थापित करने की है और कितने वर्षों में ?

श्री राज बहादुर : यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या इतना ही जवाब मेरे प्रश्न का है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सूचना इस की प्राप्त नहीं है।

Shri Hem Barua: On a previous occasion, one of his predecessors, Dr. Gopala Reddi, gave that information on the floor of the House, that the Chinese are operating about 64 transmitters all along the NEFA border.

Mr. Speaker: Let him write to me. I would like to find out.

श्री राज बहादुर: हिन्दी का उत्तर हिन्दी में देना था। अभी इन्फार्मेशन मेरे पास नहीं है।

12.00 hrs.

Short Notice Questions

Achievements of Third Five Year Plan

+

SNQ. 5. Shri Madhu Limaye:
Shrimati Renu Chakravartty:
Shri Bade:
Shri D. C. Sharma:
Shri Manoharan:
Shri Tulshidas Jadhav:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Mohammed Koya:
Shri Tridib Kumar Chaudhuri:
Shri A. V. Raghavan:
Dr. U. Misra:
Shri Indrajit Gupta:
Shri Prabhat Kar:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Rameshwaranand:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the estimate of the 'Economic Times' that in 1965-66, the real *per capita* and national incomes in India have fallen by 7·1 and 4·7 per cent respectively;

(b) whether it is a fact that in terms of real *per capita* income, the achievement of the Third Five Year Plan has been practically nil;

(c) if so, whether the Planning Commission have carried out a thorough post-mortem of the Third Five Year Plan before finalising the Fourth Five Year Plan with a view to avoiding repetition of this failure; and

(d) the main conclusions of this post-mortem?

The Minister of Planning and Social Welfare (Shri Asoka Mehta): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). It is true that owing to a sharp fall in the agricultural pro-

duction and slow rate of growth in the industrial sector, the *per capita* and national income for 1965-66 is likely to show a fall as compared to those for 1964-65. Official estimates are still in preparation, and it is not, therefore, possible to give a precise quantitative estimate of the fall. The Planning Commission's assessment of the results of the Third Plan will be incorporated in the Draft Outline of the Fourth Five Year Plan, which will be presented to the Parliament during this session.

श्री मधु लिमये : क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर गया है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना में शुरू से औद्योगिक प्रगति और खेती की पैदावार की स्थिति कुछ ऐसी खराब रही है कि उसी समय चीन ने हमारे देश पर हमला किया और वही साल था जिस वक्त राष्ट्रीय आमदनी में और फी आदमी आमदनी में बिल्कुल वृद्धि नहीं हुई, अथवा वह नहीं के बराबर हुई थी। यदि इस बात की ओर उन का ध्यान गया है तो क्या मंत्री महोदय इस बात की खोज करेंगे और सदन के सामने विवरण रक्खेंगे कि क्या वजह है कि इतना पैसा लगाने के बाद भी उत्पादन नहीं बढ़ रहा है और फी आदमी आमदनी तृतीय पंच वर्षीय योजना में नहीं के बराबर बढ़ी है या बिल्कुल नहीं बढ़ी है ?

श्री अशोक मेहता : इस सवाल के ऊपर हमारा जो दो या तीन साल का तजुर्बा था उस के अनुसार प्लैनिंग कमिशन ने 'मिड-टर्म ऐप्रेजल' पार्लियामेंट के सामने रक्खा था। माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारी सब से बड़ी दिक्कत और कमजोरी ऐग्रिकल्चर प्रोडक्शन में रही है। 1964-65 के एक साल को छोड़ कर, पांच में से चार साल तक लगातार कोई वृद्धि नहीं हो पाई और आखिरी साल में हम काफी पीछे गये। उस के कई सबब बार बार सदन के सामने आये हैं और अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उन को पेश करने के लिये तैयार हूं। जहां तक इंडस्ट्रीज का सवाल है, हमारी केपैसिटीज बढ़ती रही है और काफी बढ़ी हैं। कई हिस्सों में उत्पादन में भी काफी तरक्की हुई। लेकिन आम तौर से फौरन एक्सचेन्ज की मुसीबत इतनी काफी बढ़ गई है पांच सालों में कि बढ़ती हुई केपैसिटीज में से हम उत्पादन हासिल नहीं कर पाये।

श्री मधु लिमये : मेरे प्रश्न का असली हिस्सा था कि क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर गया कि चीन का हमला भी उसी समय में हुआ है जब योजना के बारे में और पैदावार के बारे में सरकार की अयोग्यता प्रस्थापित हो चुकी थी। इन दोनों में जो रिश्ता है उस की ओर भी क्या मंत्री महोदय का ध्यान गया है ?

श्री अशोक मेहता : मेरी समझ में नहीं आता है कि माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं। इन पांच सालों में जो हमारी आर्थिक हालत रही है वह आप के सामने है। इस में क्या कमजोरियां हैं, और क्यों हैं, इस के बारे में भी मैं बतला सकता हूं। लेकिन चीन ने जो हमला किया उस का एक ही खास नतीजा हुआ कि हमारे डिफ्रेन्स एक्सपेन्डीचर में काफी वृद्धि हम को करनी पड़ी और इसलिये एकानमी में जो स्ट्रेन्स ऐंड स्ट्रेन्स थे वे सब से ज्यादा बढ़े।

श्री मधु लिमये : यह आप ने क्या बतलाया, मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कहना है कि जब भारत की पैदावार घट रही थी और हम सफल नहीं हो रहे थे, उसी वक्त चाइना ने भी हमला किया। इन दोनों में क्या आप कोई संबंध देखते हैं ?

Shri Asoka Mehta: How do I know about it? How can the Planning Commission or the Planning Minister answer this question?

श्री मधु लिमये : तो इस का जवाब आप नहीं दे सकते हैं। और अगर आप नहीं

दें सकते तो प्रधान मंत्री हैं उनको दिलवाइये । क्या प्रधान मंत्री हमारे किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देंगी । मेरे साथ क्यों नाराजगी है। यह कोई मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है। वह प्रधान मंत्री हैं। सदस्य लोग जो सवाल पूछते हैं वह इत्तला हासिल करने के लिये पूछते हैं . . .

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अब दूसरा सवाल करें।

श्री मधु लिमये : क्या मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आयेगा। यह बाद में आयेगा या कब आयेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि इस का जवाब मिनिस्टर नहीं दे सकता।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, आप इस का जवाब दिलवाइये। आज नहीं आयेगा तो क्या कल परसों आयेगा ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप दूसरा सवाल पूछिये।

श्री मधु लिमये : मैं जानना चाहता हूं कि तृतीय पंच वर्षीय योजना की जो घोर और पूरी असफलता है उस को मद्देनजर रख कर क्या चौथी पंचवर्षीय योजना इस आधार पर बनाई जायेगी कि उस में जो फजूल खर्ची है, चालू खर्च और आमदनी में, चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो या गैर-सरकारी क्षेत्र हो, जो बहुत बड़ा फर्क है उस को घटा कर और सीमा में लाकर केवल पैदावार बढ़ाने का और पूंजीकरण का काम किया जाये ?

श्री अशोक मेहता : हमारे तजुर्बे से जो बातें निकली हैं उन के ऊपर ध्यान दे कर फोर्थ फाइव इयर प्लैन बनाई जा रही है। यह बात हो सकती है कि कई सवाल हैं जिन के बारे में हमारी अमली नीति क्या होनी चाहिये उन के सम्बन्ध में कोई आखिरी जवाब हम इस डाकुमेंट में या आउटलाइन में नहीं दे पायेंगे । मिसाल के तौर पर माननीय सदस्य ने पूछा, अगर मैं ठीक से समझ पाया हूं तो, कि इनकम पर कोई सीलिंग लगाई जायेगी या नहीं । यह ऐसा सवाल है जिस के ऊपर सिर्फ प्लैनिंग कमिशन के अन्दर विचार नहीं हो सकता है । इस पर ज्यादा खोल कर अगर ज्यादा जगहों पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो सुझाव हैं, जिन को हमने पेश किया है, उन को हमने डाकूमेंट में पेश किया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन का यह सवाल है कि जो चालू खर्च है जिस को अवायेड किया जा सकता है और एलिमिनेट किया जा सकता है उस के बारे में क्या यह कोशिश हो रही है कि उस को बन्द किया जाये ।

श्री अशोक मेहता : जहां तक एकानमी का सवाल है, जो सजेशन्स हम को देने थे हम दे रहे हैं । सरकार को जो करना है वह भी हो रहा है और वह सदन के सामने है ।

अध्यक्ष महोदय : दूसरी बात खर्च और आमदनी के फर्क पर सीमा. . . .

श्री अशोक मेहता : उस के बारे में हम कोई ठोस प्रोग्राम पेश नहीं कर सकते । लेकिन कुछ मोटी बातें जो हम सामने रखना चाहते हैं, उन को मैं बतलाऊंगा । अगर उन को मंजूर कर लिया गया तो उस पर काम किया जायेगा।

श्री मधु लिमये : उन्होंने कहा कि योजना आयोग सीमा रखने के बारे में फैसला नहीं कर सकता है यह तो उन की दुविधा वाली बात हो गई । वह सरकार के अन्दर हैं, योजना मंत्री भी हैं और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप इनकम और एक्स्पेंडिचर की कोई सीमा रख रहे हैं, यह पूछा गया था क्योंकि आप सरकार के मंत्री भी हैं ।

Shri Asoka Mehta: I have replied to it; as far expenditure is concerned .....(*An Hon. Member*: Personal expenditure).... As far as that is concerned, certain policies are being pursued today and certain taxation and other measures and various policies are being pursued.... (*Interruptions.*) That is your view.

श्री मधु लिमये : क्या आपकी तृतीय पंच वर्षीय योजना सफल हो गई ?

डा० राम मनोहर लोहिया : वह भूल जाते हैं कि वह मंत्री हैं । वह समझते हैं कि वह खाली एक कर्मचारी हैं ।

Shri Asoka Mehta: There is only the outline; it is not the final document. In the outline while in some areas we have gone into great details in certain areas and policies we have raised certain issues on which the national development council will have to give its direction. Until it is done, it is not possible for us to finalise it. There are the stages; there is the outline stage, there is the final report stage. By the final report stage, we hope and trust that this will be done.

श्री रामेश्वरानन्द : क्या और लोगों को मौका नहीं मिलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : दो सवालों में ही दस मिनट लग गए ।

श्री मधु लिमये : जवाब ठीक आये तो एक मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा ।

Shri D. C. Sharma: In view of the fact that the Third Plan had been signalised more by shortfalls than by its achievements, in view of the fact also that most of the members of the planning Commission are going to seek elections to the Lok Sabha to get seats on the treasury benches if possible and in view of the fact also that the midterm appraisal painted a dismal picture which has become more dismal now, will the Government take a look at the constitution of the Commission so that it is better able to collate its policies with the ministries concerned either at the central level or at the state level?

Shri Asoka Mehta: I am not aware of any of my colleagues wanting to fight the election or wanting to get on to the Treasury Benches. Secondly, as for the role of the Planning Commission or the work it has to do, it is also one of the matters which is already being looked into by the Administrative Reforms Commission.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं प्रधान मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि योजना आयोग की इन भारी असफलताओं को ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार प्लानिंग कमिशन के प्लानिंग का भी कोई विचार कर रही है, यदि हां, तो कब तक और कैसे यह हो जायेगा ?

Shri Asoka Mehta: I have already answered that question that the Administrative Reforms Commission is already looking at the role and function of the Planning Commission.

श्री स० मो० बनर्जी : पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं की नाकामयाबी के बाद अब चौथी योजना को कामयाब करने के लिये क्या यह सच है जो अखबारों में निकला है :

"Freezing of salary of Government staff proposed: The Planning Commission has proposed that the salaries of Government employees should not be increased in the Fourth Plan unless the revenue receipts rise at a faster rate than envisaged at present."

यदि यह बात सच है कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों को घटा कर या उन को न बढ़ा कर इनफ्लेशन को रोका जा सकता है तो मैं यह जानना

चाहता हूं कि श्री गजेन्द्र गडकर साहब जैसे महान व्यक्ति का जो कमिशन बिठाया गया है, उन को उसका चेयरमैन बनाकर ख्वामख्वाह बेवकूफ बनाने की क्य जरूरत थी ?

अध्यक्ष महोदय : बेवकूफ किस को बनाने की आप बात आप कह रहे हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : श्री गजेन्द्र-गडकर साहब को . . .

अध्यक्ष महोदय : ऐसा तो नहीं कहना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं वापिस लेता हूं ।

यह जो कमिशन बिठाया है जिसमें गजेन्द्रगडकर साहब हैं, बी० एन० गांगुली साहब हैं और रंगाचारी साहब हैं इसको बिठाने की क्या जरूरत थी ? वाकई में यह फैसला अगर गवर्नमेंट ने ले लिया है तो कमिशन क्यों बनाया गया है और क्यों सरकारी कर्मचारियों को धोखा दिया जा रहा है ?

Shri Asoka Mehta: I do not agree with the conclusions drawn by the hon. Member that the three plans had been a failure. When the proper time comes, I shall be able to explain the ways and wherefores of my reasonings. Secondly, as to what taxation the plan document is going to suggest, I am not in a position to indicate anything just now because, as I pointed out on earlier occasions, this matter is still to go before the Cabinet and the national development council. Only then it will come before Parliament. Lastly, the Gajendragadkar commission has been appointed to consider the question of dearness allownace; it is not a question of salaries. What suggestions we have to make on salaries will be in corporated when it comes before this hon. House. I would like to ask the hon. Members through you not to be influenced by unauthorised reports that appear in the Press.

Shri S. M. Banerjee: Sir....

Mr. Speakr: He has given the answer.

Shri S. M. Banerjee: My question was whether this news is correct, this news in the *Times of India*. He did not answer that question whether in the Third Plan there is any proposal to freeze the wages of Central Government employees?

Mr. Speaker: He has answered that.

Shri S. M. Banerjee: He has not said: No..... (*Interruptions*).

Dr. L. M. Singhvi: Are the government of the view that the declining rate in the economy of our country is largely due to stagnation of production and that it has been brought about by an unconscionably high tax structure and false sense of priorities? May I know what was being done to rectify this?

Shri Asoka Mehta: This again is a matter which would require a considerable amount of discussion. If savings have to be mobilised, if the whole structure of the economy is to be changed as to what should be the role of taxation in it, it is a matter which we can go into whenever you like.

As far as the priorities are concerned, this question has been fully discussed in the document and any time that the House goes into this document, it will be able to offer its comments. It is a sovereign body and it can change the document if it so desires.

श्री त्यागी : पिछले चन्द सालों से अन्न की कमी के कारण भारतवर्ष को मजबूरन जगह जगह से अन्न मांगना पड़ा है जिसकी वजह से भारत का प्रेस्टीज और इमेज बहुत नीचे चला गया है। मैं जानना चाहता

हूं कि क्या इस बार प्लानिंग कमिशन ने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिस से कि एग्रीकलचर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए और गांव गांव में जहां पर सिंचाई का इंतजाम नहीं है वहां सिंचाई का इंतजाम कर दिया जाए ताकि दो साल के अन्दर अन्दर हम इस लायक हो जाएं कि हमें बाहर से अन्न न मंगाना पड़े ?

श्री अशोक मेहता : जितनी हद तक माइनर इरिगेशन के काम को बढ़ाया जा सकता है उतनी हद तक उस में फार्नेइशियल प्राविजन किया गया है । एग्रिकलचर के लिए भी तीसरे प्लान के मुकाबले में चौथे प्लान में काफी ज्यादा फाइनैंशियल प्राविजन हुआ है। जिस तरह से प्लान बनाया गया है उससे यह उम्मीद होती है कि जहां तक फूड और एग्रीकलचरल प्रोडक्शन का सबील है हम चौथे प्लान के अन्दर पूरे सैल्फ-रिलायेंट बन जायेंगे ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मंत्री महोदय के उत्तर से देश में एक जबरदस्त खलबली होगी कि सिर्फ इस साल अनावृष्टि के कारण पैदावार मे कमी नहीं हुई है बल्कि पूरे पांच सालों मे खेती की पैदावार बहुत धीमी या खराब रही है । ऐसी अवस्था मे मंत्री महोदय और उन की सरकार ने जो उर्वरक नीति बनाई है वह बहुत खतरनाक मालूम होती है क्योंकि सब से पहले जल नीति होनी चाहिए । जल नीति हो क्या इसके लिए मंत्री महोदय अगले पांच सालों में भारत की जो अभी इस समय 26 करोड़ एकड़ बिना पानी के भूमि है उस में से कम से कम बीस करोड़ एकड़ में —चार करोड़ एकड़ हर साल— किसी न किसी रूप से पानी देंगे, फिर चाहे जैसा पानी दें ? क्या कोई ऐसी नीति बनाई है उन्होंने ?

श्री त्यागी : आपकी इस बात में हम आपके साथ शरीक होते हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : तब इधर आ जाओ, उधर क्यों बैठे हुए हो ?

(इंटरेपशंज)

Mr. Speaker: Order, order. I have no seats to spare; I can only allow exchange of seats.

डा० राम मनोहर लोहिया : किसी दिन जरा ताव से सब सीट बदली जाएंगी तब मजा आ जाएगा ।

श्री अशोक मेहता : दो तरह से पानी का इंतजाम किया जा सकता है । एक तो मेजर और मीडियम इरिगेशन स्कीम्ज हैं । काफी स्कीम्ज इस वक्त ये चल रही हैं । इनको तेजी से पूरा करने और इन का फायदा चौथे प्लान में लेने की कोशिश की जा रही है । दूसरा तरीका है माइनर इरीगेशन का । माइनर इरिगेशन के अन्दर जितनी हद तक एडमिनिस्ट्रेटिवली इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है, उस का कुछ अंदाजा रख कर उसके बारे में भी काफी बड़े पैमाने पर प्राविजन किया गया है।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, ठीक तरह से और ठोस जवाब दिलाइये । इस वक्त 26 करोड़ एकड़ भूमि बिना सिंचाई की है । क्या मंत्री महोदय थोड़ा सा बतायेंगे कि इस में कितनी भूमि को, दस करोड़ एकड़ को, पंद्रह करोड़ एकड़ को या बीस करोड़ एकड़ को चौथी योजना में वे पानी की सुविधाय दिला सकेंगे ?

श्री त्यागी : रुपया मंजूर किया है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जाए जहन्नुम में रुपया ।

श्री अशोक मेहता : मैंने बार बार कहा है कि कोई भी डिटेल्ज के बारे में, मैं आखिरी बात इस वक्त हाउस के सामने नहीं रख सकता हूं।

डा० राम मनोहर लोहिया : कुछ तो कहो । फिर आप, अध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि बहुत देर होती है और 20 मिनट हो गए हैं ।

Shri Tridib Kumar Chaudhuri: In view of the current controversy raging for some time about a big Plan and a small Plan in the background of the Fourth Plan outline, it seems that the mind of the Government is working in terms of a big plan. In the light of the so-called achievements of the third plan and specially in the light of the experience of all of us that agricultural production has lagged behind and the expansion of industrial capacity has not been properly utilised, what are the precise terms on which the Government are thinking and even if they decide on a big plan, how do they propose to ensure that the same fate would not overtake the Fourth Plan also? Is there any rethinking on the part of the Planning Commission in this matter?

Shri Asoka Mehta: It is difficult to define precisely what is a big plan and what is a small plan.

Shri Tridib Kumar Chaudhuri: Only yesterday the Prime Minister said something about the big plan. She should know it.

Shri Asoka Mehta: The outlay of the plan that is sought to be presented will be lower than what we had indicated in the memorandum. This plan, as the Prime Minister made it clear yesterady, is the minimum in terms of the requirements of the country and we believe the nation is capable of putting forward the effort needed to put it through. It has been said that many difficulties have been encountered during the implementation of the third plan and it is asked whether care has been taken to see that these difficulties will not continue to dog our footsteps in the Fourth Plan also. All that I can say is that both in drawing up the programmes and in organising the implementation, adequate care is being taken. I am sure the hon. member realises that when we talk of the plan, we are thinking in terms of millions and millions of our people all over the country in fields, factories and offices putting forward their share of effort and discharging their part of the responsibility. No single body or individual can give any kind of guarantee. But we hope that we will be reviewing this plan from year to year and if there are any difficulties or mistakes, they would be quickly corrected. (*Interruptions*).

Mr. Speaker: Calling Attention—Mr. Kamath.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): On a point of order, Sir, on the Calling Attention Notice.

Mr. Speaker: On this one which I have called?

Shri S. M. Banerjee: Not this one.

Mr. Speaker: Let me take up this one.

श्री किशन पटनायक : अध्यक्ष महोदय, मैं भी सवाल पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं और किसी माननीय सदस्य को नहीं बुला सकता हूं ।

श्री किशन पटनायक : इस में मेरा नाम भी है । जब दूसरे माननीय सदस्यों का कोई सवाल होता है और उसमें मेरा नाम नहीं होता है तब तो बुलाने का सवाल ही नहीं उठता है । मैं बार-बार उठ रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन आप ने मुझे अवसर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह झगड़ा न करें ।

श्री किशन पटनायक : झगड़ा न करने से आप कहां मौका देते हैं ?

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री किशन पटनायक : मेरा पायंट आफ आर्डर है । आप पूरक प्रश्न किस को पूछने देते हैं, इस बारे में आप हम को

हमेशा दुविधा में रखते हैं। उस के बारे में आप के पास कोई नीति या सिद्धान्त है या नहीं, यह आप हमें साफ़ नहीं करते हैं। जब किसी सवाल में हमारा नाम नहीं रहता है, तब तो आप बिल्कुल बचाते ही नहीं हैं और जब किसी सवाल में हमारा नाम रहता है हम बार-बार खड़े होते हैं, आपकी आंखों के सामने खड़े होते हैं, तब भी आप नहीं बुलाते हैं। इस तरह से नहीं चल सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफ़सोस है कि इस मेम्बर साहब के दिल में यह खयाल आया है कि मैं इन के बारे में जान-बूझ कर फ़र्क करता हूं।

श्री फिरोज गांधी : फ़र्क हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : अगर हुआ है, तो तो मैं क्या कर सकता हूं ? मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री मधु लिमये : अगर आप उनको बुलायेंगे, तो उन की शंका दूर हो जाएगी।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि वह कहते हैं कि हम इस योजना में ध्यान रखेंगे और कर्मचारियों को देखते रहेंगे और इस योजना को सफल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब वह पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में यह काम नहीं कर पाये, तो हम यह आशा कैसे करें कि अगली योजना में वह इसको करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह पहले भी कोशिश करते रहे हैं और अब भी कोशिश करेंगे।

श्री रामेश्वरानन्द : पहले के बारे में वह मान गए हैं कि वह असफल रहे हैं।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

Support to GDR for U.N. Membership

*305. **Shri H. N. Mukerjee:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Government of German Democratic Republic has sought India's support for her application for U.N. membership; and

(b) if so, the attitude of Government thereon?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) No, Sir. On the 8th March, 1966 the Head of the G.D.R. Trade Representation in New Delhi handed over to the Ministry of External Affairs a copy of Memorandum which the G.D.R. Government submitted to the United Nations on the 28th February, 1966 for membership.

(b) According to established procedure an application for new membership of U.N. has to be considered by the U.N. Security Council. India is not a member of the Security Council and will, threfore, not come into the picture for some time. Meanwhile, we will study the question carefully.

Indo-Ceylonese Agreement on Stateless Persons

*309. **Dr. Ram Manoha Lohia:**
Shri Sezhiyan:
Shri R. S. Pandey:
Shri Liladhar Kotoki:
Shri R. Barua:
Shri P. C. Borooah:
Shri M. K. Kumaran:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ceylon Government have not honoured the Shastri-Srimavo agreement on stateless persons of the Indian origin;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the position of 1,50,000 stateless persons of the Indian origin, who were left out of the purview of this agreement?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) No, Sir. Both the Governments have been cooperating in implementing the agreement.

(b) Does not arise.